

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1982}

**THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICAL INSTITUTIONS
(ACQUISITION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1982**

[U. P. Act No. 18 of 1982]

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1982]

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 फरवरी, 1982 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 16 मार्च, 1982 की बैठक में स्वीकृत किया।}

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 7 अप्रैल, 1982 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 17 अप्रैल, 1982 को प्रकाशित हुआ।}

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली कतिपय गैर सरकारी संस्थाओं का अर्जन और प्रबंध करने, ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

चूंकि राज्य में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली अनेक चिकित्सा संस्थाएं केवल धन लोलुपता के अभिप्राय से चलायी जा रही हैं;

और चूंकि इन संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षा का स्तर, सज्जा और अध्ययन की सुविधा अपेक्षित स्तर की नहीं है;

और चूंकि इनमें से अधिकांश संस्थाएँ राज्य में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं और इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का भाग्य अनिश्चित रहता है;

और चूंकि ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उसमें शिक्षा के स्तर और उपचार में सुधार करने की दृष्टि से कतिपय वर्तमान संस्थाओं का अर्जन करना और शेष संस्थाओं को बन्द करना आवश्यक है;

और चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित करना समीचीन है;

अतएव, अब भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय — एक

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

2— इस अधिनियम में, —

परिभाषाएं

(क) “नियत दिन” का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(ख) “आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति” का वही तात्पर्य होगा, जो उसके लिए संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 में दिया गया है;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 1 फरवरी, 1982 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. यह अधिनियम सं० 3118/चिकि०.0/पांच-13-80 दिनांक 2 जुलाई, 1982 द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1982 से प्रवृत्त किया गया।

(ग) “अनुसूचित संस्था” का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था के साथ-साथ उससे संलग्न या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी हैं;

(घ) किसी अनुसूचित संस्था के सम्बन्ध में, “सोसाइटी” का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी, न्यासी या अन्य व्यक्ति या निकाय से है, जिसमें ऐसी संस्था का स्वामित्व और उसके कार्य-कलाप का प्रबन्ध और नियंत्रण निहित हो।

अध्याय – दो अनुसूचित संस्थाओं का अर्जन

3— (1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था और उसके साथ ही—

अनुसूचित संस्थाओं का राज्य सरकार में निहित होना

(क) ऐसी समस्त भूमि, जिस पर ऐसी संस्था स्थित हो और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमि और ऐसी भूमि पर समस्त भवन, निर्माण और फिक्सचर;

(ख) ऐसी संस्था का समस्त फर्नीचर, उपस्कर, स्टोर, साधित्र, उपकरण, यंत्र, भेषज, औषधि, निर्माण-कार्य, कर्मशाला, परियोजना, आटोमोबाइल, पुस्तकें, धन और अन्य आस्तियां;

(ग) ऐसी समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत फार्म, पट्टा और समस्त अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, विशेषाधिकार, आरक्षित निधि, विनिधान, बही-ऋण (बुकडेट) और ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित भी हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसी संस्था के कार्यकलाप के प्रबन्ध के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति, न्यासी, सोसाइटी या अन्य निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रही हो;

राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेगी और पूर्ण रूप से उसमें निहित होगी और ऐसी संस्था के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जायेगी और उपयोग में लायी जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किसी सम्पत्ति और आस्ति के संबंध में प्रत्येक दान-विलेख, विन्यास, वसीयत, न्यास या अन्य दस्तावेज का, नियत दिन से, इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो वह राज्य सरकार के पक्ष में किया या निष्पादित किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक सम्पत्ति और आस्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर राज्य सरकार में निहित हो गई है, इस प्रकार निहित होने के आधार पर सभी ऋण, बाध्यता बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले भारों से मुक्त और उन्मोचित हो जायगी और ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी रीति से निर्बन्धित करने वाली किसी न्यायालय या अधिकारण को प्रत्येक कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को वापस लिया गया समझा जायगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित या विद्यमान किसी कार्यवाही या वादहेतुक को नियत दिन से, राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रखा और प्रवृत्त किया जा सकेगा, जैसा वह ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकता था यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता।

{उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982}

{धारा 4-6}

4— (1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निदेशित करे।

अनुसूचित संस्थाओं का प्रशासन

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि —

(क) एक या अधिक अनुसूचित संस्थाओं को बन्द कर दिया जायगा;

(ख) ऐसी दो या अधिक संस्थाओं को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा;

(ग) ऐसी एक या अधिक संस्थाओं के छात्रों को ऐसी किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित या आमेलित कर दिया जायगा;

(घ) ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक संस्था से दूसरी संस्था में कर दिया जायगा।

5— प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति हो, ऐसी सम्पत्ति या आस्ति कलेक्टर या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल परिदत्त कर देगा और कलेक्टर या यथापूर्वोक्त ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसा परिदान प्राप्त करने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

कब्जा देने का कर्तव्य

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति से संबंधित कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज हो, उनका लेखा-जोखा कलेक्टर को या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, देने का जिम्मेदार होगा।

(3) इस अधिनियम में दिए गए अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों का, जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की गयी है, कब्जा लेने के लिए ऐसी समस्त कार्यवाही करे, जो आवश्यक और विधिपूर्ण हो।

6— (1) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी, जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित संस्था में या उसके कार्यकलाप के संबंध में नियोजित हो, नियत दिन से, राज्य सरकार का, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायगा और अपना पद उसी कार्यावधि के लिये उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेन्शन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा, जैसे धारण करता, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता और इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित न कर दिया जाय :

अध्यापक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे

परन्तु यदि ऐसा अन्तरण किसी ऐसे अध्यापक या अन्य कर्मचारी को स्वीकार न हो तो वह नियत दिन से एक मास के भीतर राज्य सरकार को इस आशय की सूचना देगा और तदुपरान्त उसका नियोजन नियत दिन से समाप्त हो जायगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार की जाती है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित का हकदार होगा —

[उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982]

[धारा 7]

(क) स्थायी कर्मचारी की स्थिति में तीन मास के वेतन के बराबर और किसी अन्य कर्मचारी की स्थिति में एक मास के वेतन के बराबर धनराशि; और

(ख) अन्य सुविधाएं, यदि कोई हो, जो ऐसी संस्था में उसकी विगत सेवाओं के कारण उसे प्राप्त होती, यदि उसके नियोजन की समाप्ति इस प्रकार न की गई होती।

(2) उपधारा (1) अधीन किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या सेवा समाप्ति से वह संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किसी अनुसूचित संस्था में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के पद में कोई रिक्ति होती है और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था में (अनुसूचित संस्था से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसी कोटि या श्रेणी के किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन करता है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते वह ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करता हो।

7— (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में किसी अनुसूचित संस्था के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें दी गयी वेतनवृद्धि की यथार्थता का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार किसी अधिकारी को नाम—निर्दिष्ट कर सकती है या कोई समिति नियुक्त कर सकती है और यदि ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और प्रभावित अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों से इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, कोई नियुक्ति या वेतन वृद्धि राज्य सरकार को यथार्थ न प्रतीत हो तो वह, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की, यथास्थिति, सेवा समाप्त कर सकती है या वेतन वृद्धि को रद्द कर सकती है और ऐसी प्रत्येक सेवा—समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे।

कतिपय नियुक्तियों आदि का पुनर्विलोकन

(2) अपने स्वामित्वाधीन किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, किसी सोसाइटी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या सम्भरण के लिये की गयी प्रत्येक संविदा, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के दिन को और उसी दिन से प्रभावी न रह जायगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थन न कर दिया जाय और ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में राज्य सरकार उसमें ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है, जिसे वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार तब तक किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में त्रुटि नहीं करेगी और न उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करेगी —

(क) जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि ऐसी संविदा अनुसूचित रूप से दुर्भर है या असदभावपूर्वक की गयी है या राज्य सरकार के हितों के लिये हानिकर है; और

(ख) जब तक कि संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय।

अध्याय – तीन

नई संस्थाएं खोलने और नये छात्रों को भर्ती करने का निषेध

8— धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् —

नई संस्थाएं खोलने पर
निर्बन्धन

(क) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण कार्य का भार लेने या उसके संचालन, व्यवस्था या प्रस्थापना की प्रव्यंजना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे खुलवायेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेगा;

(ख) ऐसी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में चाहे फीस का भुगतान करने पर या ऐसे भुगतान के बिना, न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्थापना करेगा;

(ग) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के संबंध में कोई दान, अभिदान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) नहीं लेगा;

(घ) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से व्याख्यान, परीक्षा के लिए तैयार कराने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रबन्ध करेगा और न यह प्रकट करेगा कि ऐसा प्रबंध किया गया है।

9— आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली कोई चिकित्सा संस्था, जो नियत दिन के पूर्व स्थापित हुई हो, नियत दिन को ऐसी संस्था में नाम-निवेशित छात्रों को नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि में निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रोन्नति के रूप में भर्ती कर सकती है और उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् धारा 8 के उपबन्ध प्रत्येक संस्था पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

छात्रों की भर्ती पर निर्बन्धन

10— धारा 8 या धारा 9 की कोई बात आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक के अपनी रुचि की किसी शिक्षा संस्था को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के
सम्बन्ध में व्यावृत्ति

11— धारा 8 और 9 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 8 और 9 के उल्लंघन
के लिए शास्ति

अध्याय – चार

प्राकृतिक और योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थायें

12— (1) राज्य सरकार के लिए प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था की स्थापना, उसके अनुरक्षण, प्रबन्ध और कार्य को नियमों द्वारा विनियमित करना विधिपूर्ण होगा।

प्राकृतिक और योग
चिकित्सा से संबंधित
संस्थाओं का विनियमन

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् —

[उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982]

[धारा 13-15]

(क) ऐसे नियमों के प्रारम्भ के दिनांक को प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण;

(ख) ऐसी नई संस्थाएं खोलने या स्थापित करने के लिए, जिसमें प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान किया जाना हो, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए उपबन्ध;

(ग) ऐसी शर्तें और निबन्धन आरोपित करना, जिन पर खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं को पूर्ववत् बने रहने की अनुमति दी जायगी;

(घ) नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं का नियतकालिक निरीक्षण करने के लिए उपबन्ध;

(ङ) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं के प्रबन्धतंत्र से ऐसी सूचना, विवरण-पत्र या विवरणियां ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, मांगने की शक्ति प्रदान करना;

(च) उन व्यक्तियों पर, जो ऐसे नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करे या तदधीन जारी किये गये किसी विधिपूर्ण निदेश का अनुपालन करने में विफल रहे, शास्ति आरोपित करने के लिए उपबन्ध।

अध्याय — पाँच

प्रकीर्ण

13— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरी की किसी डिक्री या आदेश में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव होगा

14— प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो —

शास्ति

(क) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी सम्पत्ति या आस्ति को अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी सम्पत्ति या आस्ति को धारा 5 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए, राज्य सरकार से दोषपूर्ण रीति से रोकता है, या

(ख) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी सम्पत्ति या आस्ति पर सदोष कब्जा लेता है या बनाये रखता है, या

(ग) किसी अनुसूचित संस्था के संबंध में अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज धारा 5 की उपधारा (2) का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर रोकता है या उनका लेखा-जोखा देने में विफल रहता है, या

(घ) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी सम्पत्ति का सदोष उपयोग करता है, उसे हटाता है, या नष्ट करता है,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा।

15— (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य-संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा है, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

कम्पनी द्वारा अपराध

{उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982}

{धारा 16— अनुसूची}

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना नहीं किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए पूर्णरूपेण सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

16— इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

17— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये किसी लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा।

अपराध का संज्ञान

18— राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

अनुसूची

{धारा 2 (ग) देखिये}

क्रम संख्या	संस्थाओं के नाम
1	आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी।
2	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक आयुर्वेदिक कॉलेज, हंडिया (इलाहाबाद)।
3	तक मिल—उत्तीब कालेज, लखनऊ
4	यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।

**THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICAL INSTITUTIONS
(ACQUISITION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1982¹**

[U. P. ACT NO. 18 OF 1982]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 10, 1982, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 16, 1982.]

Received the assent of the President on April 7, 1982 under Article 201 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated April 17, 1982.]

**AN
ACT**

to provide for the acquisition and management of certain non-government institutions imparting instruction in Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of medicine, to provincialize education in such systems of medicine, to regulate the imparting of instruction in naturopathy and Yoga Therapy and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, a large number of medical institutions imparting instruction in the Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of Medicine are operating in the State with mercenary motives;

AND, WHEREAS, the standard of education, equipment and facility for studies obtaining in these institutions are not up to the mark;

AND, WHEREAS, most of these institutions are not affiliated to any University in the State and the fate of students obtaining instructions in these institutions remains uncertain;

AND, WHEREAS, with a view to provincializing education in such systems of medicine and improving standard of education and treatment therein, it is necessary to acquire certain existing institutions and to close down the rest;

AND, WHEREAS, it is expedient to regulate the imparting of instruction in naturopathy and Yoga therapy;

NOW, THEREFORE, it is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :

**CHAPTER I
Preliminary**

Short title and commencement	1-	(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Indian Medical Institutions (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1982. (2) It shall come into force on such date ² as the State Government may, by notification ² , appoint in this behalf.
Definitions	2-	In this Act,--- (a) 'Appointed day' means the date notified under sub-section (2) of section 1; (b) 'Ayurvedic and Unani-Tibbi systems of medicine' shall have the meaning assigned to it in U.P. Indian Medicine Act, 1939;

1- For Statement of Objects and Reasons. see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated February 1. 1982.

2- This Act was enforced w.e.f. July 2, 1982 vide notification no. 3118Ck-9/v-13-80, dated July 2, 1982.

(c) 'Scheduled institution' means a medical institution imparting instruction in Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of medicine specified in the Schedule together with the hospitals and dispensaries attached thereto or used in connection therewith and include all lecture rooms, laboratories, libraries, hostels and boarding houses used in connection with or as accessories to, or adjuncts of such institution;

(d) 'Society' in relation to a scheduled institution means the society, trustee or other person or body in which or unto whom the ownership, management and control of the affairs of such institution are vested.

CHAPTER II

Acquisition of Scheduled Institutions

Vesting of
scheduled
Institutions in
the State
Government

3-

(1) On and from the appointed day, every scheduled institution together with-

(a) all lands on which such institution stands and all other land appurtenant thereto, and all buildings, erections and fixtures on such lands ;

(b) all furniture's, equipments, stores, apparatuses, instruments, appliances, drugs, medicines, works, workshops, projects, automobiles, books, moneys and other assets of such institution ;

(c) all other properties, movable and immovable, including farms, leases and all rights, powers, authorities, privileges, reserve funds, investments, book-debts and all other rights and interests in or in relation to or arising out of such property as were, immediately before the appointed day, in the ownership, possession, power or control of any person, trustee, society or other body in charge of the management of the affairs of such institution ;

shall stand transferred to, and vest in absolutely the State Government and shall be applied and used for the purposes of such institution.

(2) Every deed of gift, endowment, bequest, trust or other document in relation to all or any of the properties and assets referred to in sub-section (1) shall, as from the appointed day, be construed as if it were made or executed in favour of the State Government.

(3) Subject to the provisions of this Act, every property and assets referred to in this section, which by virtue of sub-section (1) has vested in the State Government shall, by force of such vesting, be freed and discharged from any debt, obligation, mortgage, charge or lien and other encumbrances affecting it, and every attachment, injunction, decree or order of any court or tribunal restricting the use of such property in any manner shall be deemed to have been withdrawn.

(4) Subject to the provisions of this Act any proceeding or cause of action pending or existing immediately before the appointed day, by or against the society may, as from the appointed day, be continued and enforced by or against the State Government as it might have been enforced by or against such society if this Act had not come into force.

The Uttar Pradesh Indian Medical Institutions (Acquisition and
Miscellaneous Provisions) Act, 1982

[Section 4-6]

Administration of scheduled institutions	4-	<p>(1) On and from the appointed day, every scheduled institution shall be administered by the State Government in such manner as the State Government may from time to time direct.</p> <p>(2) Without prejudice to the generality of the provisions or sub-section (1), the State Government may direct that --</p> <p>(a) one or more of the scheduled institutions shall be closed down ;</p> <p>(b) two or more of such institutions shall be combined or amalgamated;</p> <p>(c) students of one or more of such institutions shall be transferred to or absorbed in any other among such institutions;</p> <p>(d) teachers and other employees of such institution shall be transferred from one institution to another.</p>
Duty to deliver possession	5-	<p>(1) Every person having possession, custody or control of any property or assets referred to in section 3 on the appointed day shall deliver forthwith such property or assets to the Collector or to such other officer of the State Government as may be authorized by the State Government in this behalf, and the Collector or such other officer as aforesaid may use such force as may be necessary for obtaining such delivery.</p> <p>(2) Any person who, on the appointed day, has in his possession, custody or control any books, papers or other documents relating to any property referred to in section 3 shall be liable to account for the same to the Collector or to such other officer or employee of the State Government as may be authorized by the State Government in this behalf.</p> <p>(3) Without prejudice to the other provisions contained in this Act, it shall be lawful for the State Government to take all such steps as are necessary and lawful for taking possession of all properties and assets which have been transferred to and vested in it under this Act.</p>
Teachers, and other employees to become employees of State Government	6-	<p>(1) Subject to the provisions of section 7, every teacher or other employee who, immediately before the appointed day is employed in, or in connection with the affairs of any scheduled institution shall become, as from the appointed day, a teacher, or other employee, as the case may be, of the State Government and shall hold his office by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held, if this Act had not come into force and shall continue to do so, unless and until his employment is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions are duly altered by the State Government :</p> <p>Provided that if such transfer is not acceptable to any such teacher or other employee, he may give intimation to the State Government to that effect within one month from the appointed day and thereupon, his employment shall stand terminated with effect from the appointed day :</p> <p>Provided further that if the employment of a teacher or other employee is terminated in accordance with the preceding proviso, such teacher or employee shall, subject to the provisions of sub-section (2), be entitled --</p>

The Uttar Pradesh Indian Medical Institutions (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1982

[Section 7]

(a) to an amount equivalent to three months salary in the case of permanent employee, and one month's salary in the case of any other employee ; and

(b) to other benefits, if any, which would have accrued to him because of his past services in such institution, if his employment had not been so terminated.

(2) The transfer or termination of the services of any teacher or other employee under sub-section (1) shall not entitle him to any compensation under the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 or any other law for the time being in force, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

(3) If any vacancy occurs in the post of a teacher or other employee in any scheduled institution at any time after the commencement of this Act, and a teacher or other employee serving in any medical institution imparting instructions in Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of Medicine (other than a scheduled institution) on the date immediately preceding the date of such commencement applies for appointment to any post' carrying the same rank, or grade, then such teacher or employee shall be entitled to preference over other applicants, provided he fulfills the minimum qualifications prescribed for such post.

Review of
certain
appointments
etc.

7-

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may nominate an officer or appoint a committee to review the genuineness of all appointments made or increments of salary given to the teachers or other employees of scheduled institution within the period of two years immediately preceding the appointed day, and if after considering the report of such officer or committee and representations that may be received in that behalf from the teachers or other employees affected, and appointment made or increment given does not appear to the State Government to be genuine, it may terminate the services of such teacher or employee or cancel the increment, as the case may be, and the provisions of sub-section (2) of section 6 shall apply to every such termination.

(2) Every contract entered into by a society in relation to any property or asset owned by it, which is vested in the State Government under section 3, for any service, sale or supply and in force immediately before the appointed day, shall, on and from, the expiry of a period of one hundred and eighty days from the appointed day cease to have effect, unless such contract is, before, the expiry of that period, ratified in writing by the State Government and in ratifying such contract, the State Government may make such alteration or modification therein as it may think fit :

Provided that the State Government shall not omit to ratify a contract and shall not make any alteration or modification therein ---

(a) unless it is satisfied that such contract is unduly onerous or has been entered into in bad faith or is detrimental to the interests of the State Government; and

(b) except after giving the parties to the contract a reasonable opportunity of being heard and except after recording in writing its reasons for refusal to ratify the contract or for making any alteration or modification therein.

CHAPTER III
**Prohibition against opening new institutions and admitting
new students**

Restriction on opening of new institutions	8-	<p>Subject to the provisions of section 9, no person other than a person authorized by the Central Government or the State Government shall, on or after the appointed day-</p> <p>(a) open, organize, maintain, manage or cause to be opened, organized, maintained or managed any institution professing to undertake conduct, provide or offer any instruction in Ayurvedic and Unani-Tibbi System of medicine ;</p> <p>(b) admit or offer admission on payment of fee or without such payment to any course of instruction in such system of medicine ;</p> <p>(c) receive any donation, subscription or fee (by whatever name called) in respect of any institution imparting instruction in such system of medicine;</p> <p>(d) make any arrangement or hold out that arrangements have been made for lecture, coaching or tuition or experiments in any laboratory with a view to imparting instruction in such system of medicine.</p>
Restriction on admission of student	9-	<p>A medical institution imparting instruction in Ayurvedic or Unani-Tibbi System of medicine established before the appointed day may admit students enrolled in such institution on the appointed day from a lower class to higher class by way of promotion during a period of five years from the appointed day, and after the said period of five years, the provisions of section 8 shall <i>mutatis mutandis</i> apply to every such institution.</p>
Savings in respect of minority institutions	10-	<p>Nothing in section 8 or section 9 shall affect the right of any minority referred to in Article 30 of the Constitution to establish and administer any educational institutions of their choice “for imparting instruction in Ayurvedic or Unani-Tibbi- Systems of Medicine or Naturopathy or Yoga Therapy”.</p>
Penalty for contravention of sections 8 and 9	11-	<p>Every person who contravenes the provisions of sections 8 and 9 shall be punishable with imprisonment for a period which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.</p>

CHAPTER IV
Instructions imparting instructions in Naturopathy and Yoga Therapy

Regulation of institutions relating to Naturopathy and Yoga Therapy	12-	<p>(1) It shall be lawful for the State Government to regulate, by rules, the establishment, maintenance, management and functioning of every institution imparting instruction in Naturopathy or Yoga Therapy.</p> <p>(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the rules referred to in that sub-section may provide for all or any of the following matters, namely—</p>
---	-----	---

The Uttar Pradesh Indian Medical Institutions (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1982

[Section 13-15]

(a) registration of institutions imparting instruction in Naturopathy or Yoga Therapy on the date of commencement of such rules;

(b) provision for obtaining prior permission for opening or establishing new institutions in which instruction in Naturopathy or Yoga Therapy is to be imparted;

(c) imposition of terms and conditions on which the institutions referred to in clauses (a) and (b) shall be allowed to continue;

(d) provision for the periodical inspection of the institutions referred to in clauses (a) and (b) by officers authorized under the rules;

(e) empowering the State Government or the officers authorized by it to call for such information, statement or returns from the management of institutions referred to in clauses (a) and (b), and on such intervals as may be prescribed;

(f) provision for imposition of penalty on persons who contravene the provisions of such rules or who fail to comply with any lawful directions issued thereunder.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

Provision of the Act to have overriding effect	13-	The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained, in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law other than this Act or any decree or order of any court, tribunal or authority.
Penalties	14-	<p>Every person who--</p> <p>(a) having in his possession, custody or control, any property or asset held for the purposes of a scheduled institution wrongfully withholds such property or asset from the State Government in contravention of sub-section (1) of section 5; or</p> <p>(b) wrongfully obtains possession of or retains any property or asset held for the purposes of any scheduled institution ; or</p> <p>(c) wilfully withholds or fails to account for any book, paper or other document in his possession, custody or control relating to a scheduled institution in contravention of sub-section (2) of section 5; or</p> <p>(d) wrongfully uses, removes or destroys any property held for the purposes of a scheduled institution;</p> <p>shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.</p>
Offences by companies	15-	(1) Where any offence under this Act is committed by a company, every person who, at time the offence was committed was incharge, of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

The Uttar Pradesh Indian Medical Institutions (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1982

[Section 16-Schedule]

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-- For the purpose of this section : -

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm, society or other association of individuals ; and

(b) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

Protection of action taken in good faith	16-	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any of its officers or other employees for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.
Cognizance of offences	17-	Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing made by the State Government or any officer authorized in this behalf by that Government.
Power to make rules	18-	The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

THE SCHEDULE
[See section 2 (c)]

Serial no.	Name of Institutions
1-	Ayurved Mahavidyalaya, Varanasi.
2-	Lal Bahadur Shastri Smarak Ayurvedic College, Handia (Allahabad).
3-	Takmil-ut-Tib College, Lucknow.
4-	Unani Medical College, Allahabad.